

जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए भूमि निवेश सुरक्षा उपाय होने चाहिए, स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियां पैदा होनी चाहिए : उमर

श्रीनगर में सीआईआई जेएंडके वार्षिक सत्र-2025 में भाग लिया

श्रीनगर

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारतीय उद्योग परिसंघ के जम्मू और कश्मीर वार्षिक सत्र-2025 शीर्षक अन्तर्द्वात् जम्मू-कश्मीर नए विकास लक्ष्यों की आकांक्षा में भाग लिया।

भारतीय उद्योग परिसंघ जेएंडके कार्डिनल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कारोबारी नेताओं, उद्योगपतियों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाकर जम्मू-कश्मीर की आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक कार्रवाइयों पर चर्चा की गई, जिससे एक मजबूत और अनुकूलपूर्ण औद्योगिक और टिकाऊ उद्यमियों परिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता और व्यावसायिक क्षमता को आगे बढ़ाया जा सके।

सत्र को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री



ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की व्यावसायिक अवसर पैदा करने के लिए बातचीत दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और महत्वपूर्ण है। यह प्रमुख मुद्दों पर आम विशिष्ट सेवाओं और रणनीतिक वैशिष्टक संबंधों के माध्यम से उद्योगों के लिए

मुख्यमंत्री ने भाग लेने वाले उद्यमियों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे, जिन्हें जनता के समग्र कल्याण और लाभ के साथ-साथ उद्योगों, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों के लिए जम्मू और कश्मीर के आगामी बजट में शामिल किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने एक आर्थिक परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार उद्यमशीलता प्रथाओं की सामना किया है। उन्होंने दस वर्षों से अधिक समय तक व्यवसायों की व्यवहार्यता को ट्रैक करने के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव करते हुए, दीर्घकालिक व्यापार स्थिरता सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।

जम्मू-कश्मीर में निवेश बढ़ाने की वकालत करते हुए, मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे निवेशों को कृषि भूमि की रक्षा करने वाले कानूनों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए और हिमाचल प्रदेश की तरह भूमि निवेश सुरक्षा उपाय होने चाहिए, जिसने उचित प्रतिबंध लगाए हैं और साथ ही यह स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियां सुनिश्चित करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने इस संबंध में एक सख्त नीति अपनाई है और जम्मू-कश्मीर में भी इसी तरह की नीति अपनाने पर जोर दिया है।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर के उद्योग की सारांश की, उन व्यवसायों को स्वीकार किया जिन्होंने पूरी तरह से सरकारी सब्सिडी पर निर्भर हुए बिना चुनौतीपूर्ण समय का जिम्मेदार उद्यमशीलता प्रथाओं की सामना किया है। उन्होंने दस वर्षों से अधिक समय तक व्यवसायों की व्यवहार्यता को ट्रैक करने के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव करते हुए, दीर्घकालिक व्यापार स्थिरता सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।

व्यवसाय करने में आसानी पर, मुख्यमंत्री ने एक वास्तविक एकल-खिड़की निकासी प्रणाली की वकालत की, जिसमें नौकरशाही बाधाओं पर चिंताओं को हल किया गया, विशेष रूप से वन और पर्यावरण बोर्डों से मंजूरी प्राप्त करने में, जो विनिर्माण विकास में शेष पृष्ठ 15 पर

गुलाम मानसिकता वाले लोग विदेशी समर्थन से भारत की धार्मिक मान्यताओं का मजाक उड़ाते हैं : मोदी

छतरपुर (मप्र)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाकुंभ पर आलोचनात्मक टिप्पणियों को लेकर नेताओं के एक वर्ष को गविवार को आड़ द्वारा लिया और कहा कि गुलाम मानसिकता वाले लोग विदेशी ताकतों के समर्थन से देश की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर हमला करते रहते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यप्रदेश के छतरपुर में बगेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान केंद्र और कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए प्रयागराज में जारी महाकुंभ को “एकता का महाकुंभ” करार दिया।

मोदी ने प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद ही रहे महाकुंभ के धार्मिक महत्व को रेखांकित किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ एक दुर्लभ खण्डोलीय संयोग के चलते 144 साल बाद ही रहा



है। बगेश्वर धाम भगवान हनुमान से जुड़ा मध्यप्रदेश के बुदेलखंड क्षेत्र में एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां हजारों लोग आते हैं। मोदी ने कहा, “नेताओं का एक वर्ष, धर्म का मखोल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है। लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमज़ोर करने की कोशिश करती दिखती हैं।

उन्होंने कहा, हिन्दू आस्था से नफरत

करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी वेश में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से धिरे ये लोग हमारे मठ, मंदिरों पर हमारे संत, संस्कृति व सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, ये लोग हमारे पर्व, परम्पराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर कीचड़ उछलने की ये हिम्मत

इंडिया ने पाकिस्तान पर दर्ज की 'विराट' जीत



दुर्बर्द्ध

चैपियंस ट्रॉफी के दूसरे लीग मैच में भारतीय टीम ने दूर्नियंट होस्ट कर रही पाकिस्तानी टीम को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। इस मैच में पहले भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को 50 ओवर से पहले ही ऑलआउट कर दिया तो दूसरी ओर प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा उत्तरकर सभी को गैरवान्वित किया है। आपके भविष्य के मैचों के लिए मेरी शुभकामनाएं।

श्रीमहाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी बुधवार को, जम्मूवासियों ने तैयारियां शुरू की



जम्मू

भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक, श्रीमहाशिवरात्रि का पर्व वर्ष 26 फरवरी, बुधवार को मनाया जाएगा। इस पावन अवसर को लेकर जम्मूवासियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और मंडिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है। जम्मू के रघुनाथ मंदिर, रणवीरेश्वर मंदिर और अन्य शिवालयों में भव्य तैयारियां चल रही हैं। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र और धूतूरा चढ़ाने के लिए श्रद्धालु जुट्टे लगे हैं। भक्तजन व्रत खेकर भगवान शिव की आराधना करेंगे और रत्न जागरण का आयोजन किया जाएगा। शहर के बाजारों में बेलपत्र, फूल, फल, पंचामृत, धूप और गंगाजल की खरीदारी

के लिए भीड़ उमड़ने लगी है। पिंडाई की दुकानों पर पेड़े और पंचामृत प्रसाद की मांग बढ़ गई है। वहाँ, कई जगहों पर शिवभक्तों के लिए भंडारे भी लगाए जाएंगे।

शिवरात्रि के अवसर पर जम्मू में शिव बारात निकाली जाएगी, जिसमें श्रद्धालु शिव-गणों की झांकी के साथ नृत्य करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का उत्सव मनाएंगे। पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मंडिरों और प्रमुख स्थलों पर विशेष निरागनी रखी जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन श्रीमहाशिवरात्रि मनाई जाती है

महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिये विशेष महत्व रखती है। श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष, महंत रोहित शास्त्री (ज्योतिषाचार्य) ने बताया कि एक वर्ष में कुल 24 एकादशी होती हैं, लेकिन प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार अधिकमास (मलमास) आने पर इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। इस वर्ष विजया एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1 बजकर 56 मिनट पर होगा, और समाप्त 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर होगा। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की सूर्योदय व्यापी एकादशी तिथि 24 फरवरी, सोमवार को पड़ने के कारण इस वर्ष विजया एकादशी व्रत 24 फरवरी, सोमवार को रखा जाएगा।

फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्मग्रंथों के अनुसार, विजया एकादशी व्रत के पुण्य से भगवान श्रीराम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। तभी से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। यदि आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको विजया एकादशी का व्रत, पूजन एवं कथा अवश्य करनी चाहिए।

इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ, जप, तप, तीर्थ स्नान और दान से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। व्रती को अपने चित्त, इंद्रियों और व्यवहार पर संयम रखना अवश्यक होता है। यह व्रत जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। व्रती अपने जीवन में अर्थ और काम से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं, दोनों के लिए लाभकारी है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन स्वर्ण, भूमि, फल, वस्त्र, मिठान, अन्न, विद्या, दक्षिणा और गौदान करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त करता है।

इस दिन भगवान श्रीगणेश, श्रीलक्ष्मीनारायण, श्रीराम, श्रीकृष्ण एवं देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है। श्रीलक्ष्मीनारायण जी की कथा एवं आरती अवश्य करें अथवा कथा श्रवण करें। एकादशी व्रत का केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है, जो मन को संयमित करता है और शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार, एकादशी के पावन दिन चालब एवं तामसिक वस्तुओं का सेवन वर्जित है। इस दिन शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनका नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर और भौतिक पर पड़ सकता है। इस दिन केवल सात्त्विक आहार ग्रहण करना चाहिए।

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर के लोग पाकिस्तान में असुरक्षित महसूस करते हैं और भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं-सत शर्मा

जम्मू

जम्मू-कश्मीर संकल्प दिवस के अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने दावा किया कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर पर ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था। 90 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। 90 के दशक से ही यह झूठ फैलाया जा रहा था कि भारतीय सेना कश्मीर के लोगों पर अत्याचार कर रही है और लोगों को आजादी मिलनी चाहिए। 22 फरवरी 1994 को



सर्वसम्पत्ति से प्रस्ताव पारित किया गया कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी लेकिन भाजपा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के

लोग भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि संकल्प दिवस पर उन्हें लगता है कि ये सभी हिस्से भारत का हिस्सा होने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम अपने सभी इलाकों को पाकिस्तान के कब्जे से वापस ले।

सत शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35ए को खट्ट करके और सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिया है कि हम पीछे नहीं हैं और हम चाहते हैं कि ये हिस्से भारत का हिस्सा बनें। उस समय भाजपा कांग्रेस के साथ खड़ी थी लेकिन अब जब प्रधानमंत्री कार्यालय

से इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो कप्रिया के कुछ नेता देश की भावना को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि आज पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर के लोग खुलेआम कहते हैं कि वे भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में महार्गी और असुरक्षा देख सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। कई युद्धों में हाने के बाद अब पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को यहाँ पाकिस्तान जैसी स्थिति बनाने के लिए भेजता है लेकिन हमारे सुरक्षा बल मजबूती से अपनी चौकियों पर डटे हुए हैं।

जम्मू-कश्मीर के बजट पर बोलते हुए सत शर्मा ने कहा कि केंद्र द्वारा आवंटित धन यहाँ के लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमने अपने विधायिकों से कहा है कि हमें बजट सत्र में रचनात्मक और सकारात्मक रूप से भाग लेना चाहिए। यहाँ की सरकार को संतुलित बजट तैयार करना चाहिए।

जम्मू और कश्मीर में मत्स्य पालन क्षेत्र में रोजगार, अर्थव्यवस्था सृजन की व्यापक संभावनाएं हैं-जावेद डार

कंगन में मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास की समीक्षा की, ट्राउट फिश फार्म मैमर के कामकाज का निरीक्षण किया

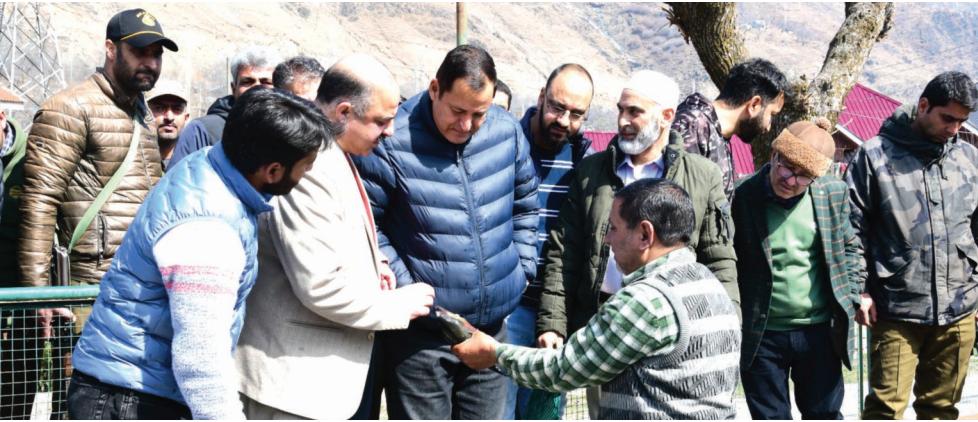
गांदरबल

कृषि उत्पादन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जावेद अहमद डार ने जम्मू-कश्मीर में मत्स्य पालन क्षेत्र में व्यापक रोजगार संभावनाओं का दोहन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मंत्री ने यह बात ट्राउट फिश फार्म मैमर की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास का आकलन करने के लिए अपनी यात्रा के दौरान कही।

कंगन के विधायक मियां मेहर अली के साथ मंत्री ने इस क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक सृजन की विशाल संभावनाओं पर प्रकाश डाला और युवाओं से मछली पालन को अपनी स्थायी आर्थिक गतिविधि के रूप में अपनाने का आग्रह किया।

निजी मछली किसानों के बीज उत्पादन की आवश्यकता पर जोर देते हुए, मंत्री ने अधिकारियों को लगातार क्षेत्र का दौरा करने और किसानों को आधुनिक मछली पालन प्रथाओं पर



शिक्षित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत एक व्यवहार्य रोजगार अवसर के रूप में इसकी क्षमता पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को मछली पालन में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया।

इससे पहले, मंत्री ने अखल, कंगन में खेबर एकाकल्चर का दौरा किया, जहां उन्होंने उन्नत रीसक्युलेटरी एकाकल्चर सिस्टम का उपयोग करके रेनबो ट्राउट को बढ़ावा देते हुए रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगी।

दौरे के दौरान, निदेशक मत्स्य पालन अब्दुल मजीद टाक, सहायक निदेशक मत्स्य पालन गांदरबल और मत्स्य पालन विभाग के अन्य अधिकारियों ने मंत्री को फार्म के संचालन के बारे में जानकारी दी।

इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ट्राउट फिश फार्म मैमर ने 2024-25 के दौरान 7 टन ट्राउट मछली का उत्पादन और

करते हुए, मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खेबर एकाकल्चर जैसी पहल न केवल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूक जलीय कृषि तकनीकों को बढ़ावा देते हुए रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगी।

मंत्री ने सुविधा का दौरा किया, इसकी पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं और टिकाऊ ट्राउट खेती के उद्देश्य से अत्याधुनिक मशीनरी की सराहना की।

निजी उद्यमियों के प्रयासों की सराहना

1.5 लाख बीज उत्पादन दर्ज किया। चालू वर्ष के लिए अपेक्षित बीज उत्पादन 2 लाख तक पहुंचने का अनुमान है।

मंत्री को निजी क्षेत्र के योगदान के बारे में भी बताया गया, जिसमें जिले के भीतर निजी क्षेत्र में चालू 140 ट्राउट और कार्प तालाबों से गांदरबल जिले में ट्राउट मछली का उत्पादन 50 टन और कार्प उत्पादन 20 टन तक पहुंच गया है।

इसके अतिरिक्त, यह बताया गया कि इस वर्ष 200 मछली पकड़ने के परमिट जारी किए गए, जिससे मनोरंजक मछली पकड़ने को और बढ़ावा मिला।

मत्स्य निदेशक ने बताया कि फार्म से जीवित चारा बीज केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सहित कश्मीर संभाग के अन्य जिलों में आपूर्ति की जा रही है।

सीयू जम्मू ने उद्यमिता विकास पर व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित

जम्मू

केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू (सीयूजे) के विषयान और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन विभाग ने कुलपति प्रो. संजीव जैन के मार्गदर्शन में उद्यमिता विकास पर व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (पीडीपी) आयोजित किया। इस कार्यक्रम में जेवेझडीआई के प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों, संकाय सदस्यों और एमबीए छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्कूल ऑफ बिजेनेस स्टडीज की डीन प्रो. जया भसीन ने किया जिन्होंने शिक्षा को उद्यमिता से जोड़ने के लक्ष्य पर जोर दिया। एमएससीएम की प्रमुख डॉ. नीलिका अरोड़ा ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और उद्यमी प्रतिभा को पोषित करने में जेवेझडीआई की भूमिका पर प्रकाश डाला। सभी नेतृत्व पर जेवेझडीआई के सेंटर फॉर न्यू एंट्रेप्राइज क्रिएशन के प्रमुख डॉ. विनोद कुमार और जेवेझडीआई के सेंटर फॉर इनोवेशन, इनक्यूबेशन और बिजेनेस मॉडलिंग के प्रभागी जाहिद अली डार ने किया जिन्होंने स्टार्टअप इकाईसिस्टम, बिजेनेस आइडिया जनरेशन और इनोवेशन रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। इंटरेक्टिव अभ्यास और चर्चाओं में छात्रों को उद्यमशीलता के अवसरों का पता लगाने और व्यवहार्य व्यावसायिक विचारों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 50 से अधिक प्रतिभागियों के साथ पीडीपी ने नवाचार, ऐपेक्षर विकास और उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा दिया।

डोडा में दुधारू मवेशी का मीट मिलने पर हुआ विरोध प्रदर्शन

जम्मू

डोडा पुलिस ने भारत रोड पर एक अंटी से दुधारू मवेशी का मीट बरामद किया। पुलिस को यह सूचना वीएचपी सदस्यों द्वारा दी गई थी। जबकि आटो चालक मौके से भागने में सफल रहा। जिसके बाद वीएचपी सदस्यों और हिंदू समुदाय द्वारा पुलिस स्टेशन डोडा के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दुधारू मवेशी के मीट की तस्करी में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की, गई। विरोध प्रदर्शन के बाद डीएसपी मुव्वालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें आशासन दिया कि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय स्टार्टअप महोत्सव का किया उद्घाटन

जम्मू

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू के गांधी नार स्थित राजकीय महिला विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दो दिवसीय महोत्सव का आयोजन सीएसआईआर-भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान (सीएसआईआर-आईआईआईएम), जम्मू द्वारा किया गया है।

महोत्सव में पूरे भारत से आए 50 स्टार्टअप्स ने कृषि, स्वास्थ्य सेवा, न्यूट्रोस्युटिकल, तकनीक, सेवा और उपभोक्ता उत्पादों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने नवाचारों और तकनीकों का प्रदर्शन किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जम्मू क्षेत्र के स्थानीय युवाओं, छात्रों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना है, जिसमें उधमपुर, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, कठुआ और सांवा जैसे जिले शामिल हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान, सीएसआईआर-आईआईआईएम ने उद्योग और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) के साथ युवाओं एवं विभिन्न शैक्षणिक ज्ञानों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। इसके अलावा, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के साथ एक अनुदान पत्र समझौता (जीएलए) भी संपन्न हुआ। नए स्टार्टअप्स को कठुआ



के घाटी स्थित औद्योगिक बायोटेक पार्क के बीआईआरएसी इनक्यूबेटर में भी शामिल किया गया।

इस महोत्सव में शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और विभिन्न शैक्षणिक

संस्थानों के छात्रों सहित कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। उल्लेखनीय प्रतिभागियों में पद्मश्री प्रो. विनोद के-

सिंह, सीसीआरयूएम के महानिदेशक डॉ. एन. जहीर अहमद, सीएसआईआर-सीआईएमएपी, लखनऊ के

निदेशक डॉ. प्रबोध कुमार त्रिवेदी, सीएसआईआर-एनबीआईआई, लखनऊ के निदेशक डॉ. अजीत कुमार शासनी और डीबीटी-बीआईआरएसी के प्रबोध निदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार शामिल थे।

जावेद डार ने स्कॉस्ट-के में 3 दिवसीय एग्रीटेक मेला गोंगुल-2025 का उद्घाटन किया

श्रीनगर

कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जावेद अहमद डार ने शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, शातीमार परिसर में कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक कृषि नवाचारों, टिकाऊ खेती प्रथाओं और उद्यमशीलता के अवसरों को प्रदर्शित करने वाले तीन दिवसीय भव्य कार्यक्रम गोंगुल 2025-10वें स्कॉस्ट-के एग्रीटेक मेले का उद्घाटन किया।

इस वर्ष का मेला विशेष है क्योंकि इसमें माध्यमिक और टिकाऊ कृषि पर जोर दिया गया है, जो समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों को दर्शाता है। मूल्य संवर्धन, जलवायु लचीलापन और कृषि-उद्यमिता पर अधिक ध्यान देने के साथ, यह कार्यक्रम नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं और किसानों को जम्मू-कश्मीर में कृषि के भविष्य को आकर देने के लिए एक साथ लाता है।

मेले में 400 से अधिक स्टॉल हैं, जिनमें नवीनतम कृषि मशीनरी, स्टीक कृषि, बीज और रोपण सामग्री की बिक्री, कृषि पशु और पक्षी प्रदर्शन किए गए हैं। मेले में पहली बार पालतू पशु शो का आयोजन किया गया, जिसमें पालतू कुत्तों और बिल्कियों ने अपने प्रशिक्षण कौशल का प्रदर्शन किया।



मुख्य अतिथि के रूप में, मंत्री ने एक भव्य समारोह में गोंगुल-2025 का उद्घाटन किया, जिसमें राजसी घोड़े भी शामिल थे। उन्होंने एग्रीटेक मेले के लिए 'गोंगुल' नाम चुनने के लिए स्कॉस्ट-के की सराहना की, जो अगली पीढ़ी को समृद्ध कश्मीरी संस्कृति से जोड़ता है। उन्होंने कश्मीर में गोंगुल (बुवाई की शुरुआत) से जुड़ी बचपन की आश्वासन दिया। उन्होंने नकली कृषि रसायनों के व्यापार की जांच के लिए सख्त कानून प्रवर्तन भी सुनिश्चित किया।

स्कॉस्ट-के उपकुलपति प्रोफेसर नजीर अहमद गई ने कहा कि गोंगुल-2025 जम्मू-कश्मीर के समग्र कृषि विकास स्तर पर जानी जाती है। एचएडीपी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल जम्मू-कश्मीर के लोगों की किस्मत बदलने वाली है। मंत्री ने क्षेत्र के कृषि परिवृश्य के परिवर्तन का नेतृत्व करने वाले स्कॉस्ट-के को जम्मू-कश्मीर सरकार का पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने नकली कृषि रसायनों के व्यापार की जांच के लिए सख्त कानून प्रवर्तन भी सुनिश्चित किया।

स्कॉस्ट-के उपकुलपति प्रोफेसर नजीर अहमद गई ने कहा कि गोंगुल-2025 जम्मू-कश्मीर के समग्र कृषि विकास

कार्यक्रम की उपलब्धियों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि स्कॉस्ट-के ने भविष्य की नवाचार आधारित खेती के माध्यम से जम्मू-कश्मीर को विकसित भारत के लिए एक मॉडल जैव अर्थव्यवस्था के रूप में देखा है। प्रोफेसर गई ने विश्वविद्यालय की पहलों को उदार समर्थन देने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार को धन्यवाद दिया।

क्रीरी विधानसभा के सदस्य इरफान हाफिज लोन ने जम्मू-कश्मीर के किसानों को सशक्त बनाने में स्कॉस्ट-के की सराहना करते हुए तेजी से घटती कृषि भूमि को संरक्षित करने और स्थानीय उपज की नियांत क्षमता को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माण और कानून प्रवर्तन की इच्छा जारी।

सोनावाड़ी विधायक हिलाल अकबर लोन ने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने किसानों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए वैज्ञानिकों की भूमिका की सराहना की। बेंगलुरु स्थित सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष अशोक दलवर्ही ने कहा कि विजन 2047 के तहत देश के निर्धारित लक्षणों को पूरा करने में जम्मू-कश्मीर की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि एचएडीपी के तहत जम्मू-कश्मीर की कृषि-परिवर्तन यात्रा के बारे में देश के बाकी हिस्सों को जागरूक करना महत्वपूर्ण है।

इस वर्ष का संस्करण कई प्रमुख उप-विषयों के इर्द-गिर्द संरचित है, जिनमें से प्रत्येक आधुनिक और टिकाऊ कृषि के विभिन्न पहलुओं में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ब्रांड बिज फेस्ट बहुग्रामीय कपनियों, एफारीओ, एसएचजी और उद्योग जगत के नेताओं के बीच नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करता है, जबकि फूड फेस्ट छेत्र स्टार्टअप और स्थानीय खाद्य उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए विविध व्यंजनों का जश्न मनाता है। स्टार्टअप और टेक शो में अभूतपूर्व कृषि नवाचारों पर प्रकाश डाला गया है, और उद्योग प्रदर्शनी में अत्याधुनिक मशीनरी और उन्नत कृषि तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है।

गोंगुल-2025 में जैविक और प्राकृतिक खेती शौं के माध्यम से टिकाऊ खेती पर भी जोर दिया गया है, जिसमें जैव-इनपुट पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और औषधीय और सुगंधित पौधों के शो में हिमालयी हर्बल खेजने की खोज की गई है। प्रसंस्कृत उत्पाद प्रदर्शनी में मूल्य-वर्धित और विविधतापूर्ण कृषि उत्पाद प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, बीज प्रदर्शनी और रोपण सामग्री प्रदर्शनी में किसानों और बागवानी के शौकीनों के लिए प्रीमियम गुणवत्ता वाले बीज और पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं।

उपमुख्यमंत्री ने जीएमसी जम्मू का दौरा किया, स्वास्थ्य सेवाओं की परेशानी मुक्त आपूर्ति का आशासन दिया



मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कंगन में अखल ब्रिज का उद्घाटन किया



कंगन (गांदरबल)

जम्मू

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चैधरी ने सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू का दौरा किया और संस्थान के कामकाज की समीक्षा की। उपमुख्यमंत्री ने वहां तैनात डॉक्टरों और पैश मेडिकल स्टाफ की संख्या का आकलन करने के अलावा मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। स्टाफ से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही निर्देश

जारी कर दिए हैं कि लोगों को सार्वजनिक सेवाओं, खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को सार्वजनिक सेवाओं की त्वरित और परेशानी मुक्त डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपमुख्यमंत्री ने कहा, "मरीजों को उनके लिए बनाई गई सुविधाओं का लाभ उठें बिना किसी चूक के प्रदान किया जाए।" उपमुख्यमंत्री के दौरे के दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अन्य वरिष्ठ संकाय सदस्य भी उनके साथ थे।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है।" उपमुख्यमंत्री ने अस्पताल के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का लाभ उठें बिना किसी चूक के प्रदान किया जाए। उपमुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया, जिससे अब अधिक सुविधा और पहचान मिलेंगी। इस अवसर पर विधायक कंगन मियां मेहर अली, उपायुक्त गांदरबल, डीडीसी सदस्य कंगन, मुख्य अधियंता आरएडबी और अन्य वरिष्ठ नागरिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में जनता दरबार लगाया

**मुद्दों को हल करने के
लिए जनता,
प्रतिनिधिमंडलों से
सीधे जुड़े**

**जनसमस्याओं के
समय पर समाधान की
प्रतिबद्धता दोहराई**

गांदरबल

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल के डाक बंगले में एक जनता दरबार बुलाया, जहां उन्होंने जिले भर के कई प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों से सीधे बातचीत की और क्षेत्र के विकास से संबंधित उनके रोजमर्ज के मुद्दों और अन्य चिंताओं को हल किया।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों और मांगों को धैर्यपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित



समाधान के लिए मौके पर ही निर्देश जारी किए। उन्होंने जिला प्रशासन से सार्वजनिक शिकायतों के निवारण को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। गांदरबल के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अपनी

निवासियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए निरंतर समर्थन और समय पर कार्रवाई का वादा किया।

गांदरबल के उपायुक्त जितन किशोर, जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, प्रतिनिधिमंडलों द्वारा उठाए गए मुद्दों

पर ध्यान देने के लिए उपस्थित थे।

बीहामा, डुडेरहामा, फतेहपोरा, शालबुग, सेहपोरा, बमलूरा, तुलमुल्ला, बरासा, थीरू, गंगेरहामा, शेरपथरी, लार, सफापोरा, गुटलीबाग और जिले के अन्य हिस्सों जैसे विभिन्न क्षेत्रों से सार्वजनिक प्रतिनिधिमंडलों

और सैकड़ों व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत कीं।

उठाई गई प्रमुख मांगों में प्रमुख स्थानों पर अग्निशमन सेवा केंद्रों की स्थापना, खेल के मैदानों का विकास, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि, जिला अस्पताल में एक सहायक सराय का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, बागवानी और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना, सिंधं नदी के किनारे सौंदर्यीकरण, झेलम की ओर से नाले के किनारे का सूटूडीकरण, और डुडरहामा नाले की ड्रेंजिंग और डीसिलिंग शामिल है।

इसके अतिरिक्त, जनता ने जिले के भीतर गोजगर के अवसर पैदा करने की मांग की। इन मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री, जो जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गांदरबल निवाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने उपायुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी वास्तविक चिंताओं का बिना किसी देरी के समाधान किया जाए।

उन्होंने जनता को आव्वासन दिया कि उजागर किए गए मुद्दों की गहन जांच की जाएगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान किया जाएगा।

**निदेशक डीआईपीआर,
कर्मचारियों ने वरिष्ठ पत्रकार
नसीर अहमद के निधन पर
शोक व्यक्त किया**

जम्मू

सूचना निदेशक नितीश राजोरा ने कोलकाता टीवी के व्यूरो चीफ नसीर अहमद के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

निदेशक ने अपने शोक संदेश में कहा कि नसीर एक वरिष्ठ पत्रकार थे, जिनका पत्रकारिता में योगदान सदैव याद रखा जाएगा।

निदेशक ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और इस कठिन समय के दौरान शोक संतप्त परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की।

इस बीच, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के कर्मचारियों ने भी अनुभवी पत्रकार नसीर अहमद के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिन्होंने काफी समय तक जी न्यूज़ के व्यूरो चीफ के रूप में भी काम किया है। कर्मचारियों ने पत्रकारिता क्षेत्र में नसीर अहमद के योगदान और डीआईपीआर के साथ उनके जुड़ाव को याद किया।

कर्मचारियों ने परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

**जम्मू में रहस्यमयी
परिस्थितियों में नाबालिग
लड़की मृत पाई गई**

जम्मू

जम्मू जिले में रविवार को एक नाबालिग लड़की अपने घर में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाई गई। बताया गया कि 14 वर्षीय 9वीं कक्षा की लड़की का शव उसके घर में रहस्यमयी परिस्थितियों में पाया गया। उन्होंने बताया कि वह जम्मू जिले के बिशनाह तहसील के महमूदपुर गांव की रहने वाली थी।

इस बीच पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।



संवाद और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनपहुंच प्रयासों को बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार लोगों की चिंताओं को सुनने और उन्हें हल करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस बीच, पूर्व आईएस अधिकारी खुशीद अहमद गन्ही के नेतृत्व में ग्रुप ऑफ कंसन्ड सिटीज़िंस के प्रतिनिधिमंडल ने राबता कार्यालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और यूनिफाइड बिलिंग बायलॉज में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया। जीसीसी सदस्यों ने सीएम से प्रस्तावित यूबीबीएल संशोधनों और शहरी

नियोजन नीतियों की समीक्षा करने का अनुरोध किया, जो अक्टूबर में निर्वाचित सरकार के कार्यभार संभालने से टीक पहले आवास और शहरी विकास द्वारा शुरू की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने उनकी आपत्तियों को सुना और कहा कि उनकी सरकार ऐसी किसी भी नीति को मंजूरी देने से पहले आपत्तियों की जांच करेगी और अन्य शहरी विकास नीतियों की जांच करेगी और कहा कि ऐसी नीतियों को मजबूत करने या उस प्रभाव पर कोई कानून लाने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श किया जाएगा।

संपादकीय

बधान पर भारी स्मार्टफोन मानसिक एकाग्रता व सेहत के लिये घातक

तकनीक के जरिये विकास की अंधी दौड़ में हम बहुत कुछ खो भी रहे हैं। इंसान कभी मशीन से संचालित नहीं हो सकता। मानवीय संवेदनाएं और अहसास कभी कृत्रिम नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई तकनीक, मशीन व उपकरण सहयोगी तो हो सकते हैं, मगर मालिक नहीं हो सकते। कमोबेश यही बात शिक्षा में तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन के उपयोग और उसके घातक प्रभावों को लेकर कही जा सकती है। निस्संदेह, शिक्षा के बाजारीकरण और नई शैक्षिक परिपाठी में मोबाइल की अपीलिंग को महोगी स्कूलों ने स्टेटस सिंबल बना दिया है। लेकिन हालिया वैश्विक सर्वेक्षण बता रहे हैं कि पढ़ाई में अत्यधिक मोबाइल का प्रयोग विद्यार्थियों के लिये मानसिक व शारीरिक समस्याएं खड़ी कर रहा है। निस्संदेह, विभिन्न ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रमों के चलते छात्र-छात्राओं में मोबाइल फोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। तमाम पब्लिक स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल अनिवार्य तक बना दिया है। कमोबेश सरकारी स्कूलों में ऐसी बाध्यता नहीं है। लेकिन वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि स्मार्टफोन एक हट तक तो सीखने की प्रक्रिया में मददगार साबित हुआ है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसमें दो गाय नहीं कि एक समय महज बातचीत का जरिया माना जाने वाला मोबाइल फोन आज दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने वाला बेद जरूरी उपकरण बन चुका है। खासकर कोरोना संकट के चलते स्कूल-कालेजों के बंद होने के बाद तो यह पढ़ाई का अनिवार्य हिस्सा बन गया। तब लगा था कि इसके बिना तो पढ़ाई संभव ही नहीं है। लेकिन नादान बच्चों के हाथ में मोबाइल बंदर के हाथ में उत्तर जैसा ही है। जाहिरा तौर पर ये उनके भटकाव और मानसिक विचलन का कारण भी बन सकता है। अब इसके मानसिक व शारीरिक दुष्प्रभावों पर व्यापक स्तर पर बात होने लगी है। यहाँ तक कि आस्ट्रेलिया समेत तमाम विकसित देश स्कूलों में मोबाइल के उपयोग पर रोक लगा रहे हैं। अब तो यूनेस्को अर्थात् संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की दुनिया में शैक्षिक स्थिति पर नजर रखने वाली टीम ने भी स्मार्टफोन के उपयोग से विद्यार्थियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर चिंता जतायी है। इसकी रिपोर्ट भारत में शिक्षा के नीति-नियंत्रणों की आंख खोलने वाली है। यूनेस्को की टीम के मुताबिक बीते साल के अंत तक कुल पंजीकृत शिक्षा प्रणालियों में से चालीस फीसदी ने सख्त कानून या नीति बनाकर स्कूलों में छात्रों के स्मार्टफोन के प्रयोग पर रोक लगा दी है। दरअसल, आधुनिक शिक्षा के साथ कदमताल की दलील देकर तमाम पब्लिक स्कूलों में मोबाइल के उपयोग को अनिवार्य बना दिया गया। निस्संदेह, आधुनिक समय में स्मार्टफोन कई तरह से शिक्षा में मददगार है। लेकिन यहाँ प्रश्न इसके नियंत्रण प्रयोग का है। साथ ही दुनिया में बेलागम इंटरनेट पर परोसी जा रही अनुचित सामग्री और बच्चों पर पड़ने वाले उसके दुष्प्रभावों पर भी दुनिया में विमर्श जारी है। जिसमें प्रश्न बच्चों की निजता का भी है। वहीं प्रश्न ज्यादा प्रयोग से बच्चों के दिमाग व शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का भी है। निस्संदेह, शिक्षकों व अभिभावकों की देखेख ये सीखने की प्रक्रिया में स्मार्टफोन का सीमित उपयोग तो लाभदायक हो सकता है। लेकिन इसका अंधाधुंध व गलत उपयोग घातक भी हो सकता है। दरअसल, स्मार्टफोन में वयस्कों से जुड़े तमाम एप ऐसे भी हैं जो समय से पहले बच्चों को वयस्क बना रहे हैं। उन्हें बौन कुठित बना रहे हैं। बड़ी चुनौती यह है कि बच्चों की एकाग्रता भंग हो रही है। बच्चों में याद करने की क्षमता घट रही है। ऐसे में जब शिक्षा में स्मार्टफोन का उपयोग टाल नहीं जा सकता, लेकिन उसका नियंत्रित उपयोग तो किया ही जा सकता है। निस्संदेह उसका उपयोग सीमित किया जाना चाहिए। संकट यह भी कि मोबाइल पर खेले जाने वाले ऑन लाइन गेम जहां बच्चों को मैटानी खेलों से दूर कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डाल रहे हैं। निश्चित तौर पर फोन छात्र-छात्राओं का सहायक तो बन सकता है, लेकिन उनके दिमाग को नियंत्रित करने वाला नहीं।

मुख्य संपादक
विवेक धर्मलम

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक विवेक धर्मलम (गली नं. 1, वॉर्ड नं. 12, नजदीक एगो पेट्रोल पंप व तहसील, बड़ी बालाणा, जम्मू व कश्मीर 181133) द्वारा शिवम आफ्टेस्ट प्रिंटिंग प्रेस, फतवारा चौक (नजदीक जैएंडके बैंक) ग्रेटर कैलाश, जम्मू (जम्मू-कश्मीर) से प्रकाशित।

संपादक
विवेक धर्मलम

फोन- 9419180421, ईमेल: admin@jammunewsmission.com
नोट: इस अंक में प्रकाशित सामग्री से संपादक प्रकाशित का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

प्राप्त स्पष्टीकरण प्रकाशित किया जाएगा। सभी विवादों का निपटारा जम्मू संभाग की सीमा के अंतर्गत आने वाली सक्षम न्यायालयों व फोरमों में ही किया जाएगा।

विकसित हो भीड़ नियंत्रण का प्रभावी तंत्र



रमेश सर्वाफ धर्मो

भगदड़ भीड़ प्रबंधन की असफलता की स्थिति में पैदा हुई मानव निर्मित आपदा है। भगदड़ प्रायः भीड़ भेरे इलाकों में किसी अफवाह के कारण भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण भी यह आपदा पैदा होती है।

देश में हम आए दिन भीड़ में भगदड़ मचने से कई लोगों के मरने की खबरें पढ़ते रहते हैं। हाल ही में महाकुंभ स्नान के दौरान प्रयागराज में भीड़ में भगदड़ के चलते 37 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वालों की भीड़ में अचानक भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई थी। यह दोनों ही दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व दुखद हैं।

देश में भगदड़ में मरने वालों की सूची बहुत लंबी है। सभी को पता है कि जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित होती वहाँ कभी भी भगदड़ मचने की स्थिति पैदा हो सकती है। मगर अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई है कि जिससे भगदड़ की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होने पाए। सरकारी भी भगदड़ होने के बाद उसको रोकने के ढोल पीट कर कुछ समय बाद शांत बैठ जाती है। मगर ऐसा कोई स्थाई तंत्र विकसित नहीं किया जाता है। जिससे भगदड़ की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होने से पहले ही सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट मिले और वह उन पर नियंत्रण कर सके।

भगदड़ भीड़ प्रबंधन की असफलता की स्थिति में पैदा हुई मानव निर्मित आपदा है। भगदड़ प्रायः भीड़ भेरे इलाकों में किसी अफवाह के कारण भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण भी यह आपदा पैदा होती है। इसमें संपत्ति से अधिक जान की क्षति होने की संभावना रहती है। भीड़ दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के वैश्विक डेटाबेस के मुताबिक सन 2000 के बाद से भारत में 50 से ज्यादा विनाशकारी सामूहिक समारोहों में दो हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इन दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रभावी भीड़ प्रबंधन तंत्र विकसित करने की बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही है। खासकर कुछ जैसे बड़े आयोजनों में इसकी काफी ज़रूरत महसूस होती है।

भगदड़ बेद खतरनाक और घातक स्थिति होती है। किसी भी जगह पर जब भीड़ उसकी क्षमता से अधिक हो जाती है और लोगों के पास निकलने का रास्ता नहीं होता है। भीड़ की वजह से लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में किसी तरह की

अफवाह या दुर्घटना होने पर भीड़ बेकाबू हो जाती है। इसे भीड़ में हलचल भी कहा जाता है। इसकी वजह से ही भगदड़ की स्थिति बनती है। इसी तरह भीड़ में हलचल का मतलब भीड़ का बेतरतीब तरीके से एक से ज्यादा दिशाओं में एक ही समय में आगे बढ़ना है। ऐसे में लोगों को चलने के लिए जगह कम होती है वो एक-दूसरे के बीच दब जाते हैं। जब लोग एक-दूसरे से बहुत नजदीक होते हैं तो 'फोर्सेंज का ट्रांसमिशन' यानी बल का संचरण हो सकता है। इस फोर्सेंज का ट्रांसमिशन को आपने भी कभी न कभी तब महसूस किया होगा जब आप एक बहुत भीड़-भाड़ वाली किसी लाइन में खड़े हो होंगे। जब पैछे से अचानक धक्का लगता है तो व्यक्ति खुद भी उस धक्के को अपने से आगे खड़े व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में अपना संतुलन बनाए रखना और अपने पैरों पर खड़े रहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।

ये पहली बार नहीं था जब किसी धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मची हो। इसके पहले भी समय-समय पर भगदड़ मचने की खबरें सामने आती रही हैं। इन घटनाओं में कई लोगों की जान भी चली गई। 27 अगस्त 2003 महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में कुंभ मेले में ज्ञान के दौरान भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई थी। 25 जनवरी 2005 को महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में मध्यारदेवी मंदिर में भगदड़ मच गई थी। जिसमें 340 से ज्यादा श्रद्धालु कुचले गए थे। 3 अगस्त 2008 हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में भगदड़ मच गई थी। 20 फरवरी 2013 को इलाहाबाद में कुंभ मेला के दौरान रेलवे ज़ंकशन पर भगदड़ मचने से 38 लोगों की मौत हो गई थी। 29 सितंबर 2017 के दिन मुंबई के एलफिंस्टन रेलवे स्टेशन में बने फुटओवर ब्रिज पर भगदड़ मचने के कारण 22 लोगों की मौत हुई थी।

हमारे देश में आए दिन जगह-जगह बड़े-बड़े धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व अन्य कई प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। जिनमें हजारों-लाखों लोग शामिल होते हैं। ऐसे ही कार्यक्रमों में जगह सी लापरवाही भगदड़ का कारण बन सकती है। ऐसे में यदि कार्यक्रम के आयोजक सावधानी बरतते हुए भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम करें तो भीड़ की दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन व प्रयागराज के महाकुंभ में भी जो भगदड़ की स्थिति पैदा हुई है उसमें प्रशासनिक चक्र रही है। एक स्थान पर अधिक भीड़ इकट्ठी होने पर यदि प्रशासन के अधिकारी सतर्कता बढ़ाते तो ऐसी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता था। आगे भी सरकार को चाहिए कि ऐसे किसी भी बड़े आयोजनों के लिए और अधिक पुख्ता व्यवस्था करें। देश में आपदा राहत बल को भी अधिक सशक्त किया जाये ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

(लेखक राजशाहन सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार है।)

सकीना इत्तू ने कुलगाम जिले के लम्पेर, चैगाम गांवों में एनटीपीएचसी का उद्घाटन किया

कुलगाम

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कुलगाम का दौरा किया और जिले के लम्पेर और चैगाम गांवों में दो नवनिर्मित नए प्रकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवनों का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर विधायक देवसर पीरजादा फिरोज़ अहमद शाह, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ कश्मीर, अतिरिक्त उपायुक्त, सहायक आयुक्त राजस्व, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित थे।

इन स्वास्थ्य सुविधाओं के उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित करते हुए, मंत्री ने पूरे जम्मू और कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सकीना ने कहा, हमारी सरकार वचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की कमियों को पाठने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा सेवाएं हर दरवाजे तक पहुंचें, जिससे दूर-दराज के अस्पतालों पर लोगों की निर्भरता कम हो।

मंत्री ने सभी के लिए, विशेषकर दूरदराज के गांवों में, सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को रेखांकित किया। ये स्वास्थ्य केंद्र इन गांवों के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्रों के लोगों को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। ये केंद्र यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी समय पर चिकित्सा देखभाल से वचित न रहे। मंत्री ने आगे बताया कि वर्तमान सरकार का ध्यान सभी के लिए गुणवत्ता पूर्ण



स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक चिकित्सा

सुविधाएं अधिक सुलभ और बेहतर ढंग से सुसज्जित हों।

इस अवसर पर देवसर विधायक पीरजादा फिरोज़

अहमद ने कहा कि इन स्वास्थ्य सुविधाओं से यहां की स्थानीय आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा।

सकीना इत्तू ने एमएमएबीएम एसोसिएटेड अस्पताल, जीएमसी अनंतनाग में कैथ लैब, नए ब्लॉक का उद्घाटन किया

अनंतनाग

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कैथीटेराइजेशन प्रयोगशाला और मिर्जा मोहम्मद अफजल बेघ मेमोरियल एसोसिएटेड अस्पताल, जीएमसी अनंतनाग के नवनिर्मित ब्लॉक-ए का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर अब्दुल मजीद भट्ट सहित जिला अनंतनाग के विधायक पीरजादा मोहम्मद सईद, रेयाज़ अहमद खान, अल्ताफ अहमद वानी और जफर अली खटाना के अलावा प्रिंसिपल जीएमसी अनंतनाग, प्रोफेसर डॉ. रुखसाना नजीब, निदेशक समन्वय न्यू मेडिकल कॉलेज, निदेशक परिवार कल्याण एमसीएच और टीकाकरण, सीएमओ अनंतनाग, चिकित्सा अधीक्षक एमएमएबीएम एसोसिएटेड अस्पताल, जीएमसी अनंतनाग के विभिन्न विभागों के प्रमुख, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

जीएमसी अनंतनाग के कैथ-लैब और



ब्लॉक ए को जनता को समर्पित करते हुए, मंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण विकास पूरे दक्षिण कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में एक नए युग का प्रतीक है, व्यायोक जीएमसी अनंतनाग अपने समर्पित कैथ-लैब प्राप्त करने वाले नव स्थापित मेडिकल कॉलेजों में पहला बन गया है। उन्होंने कहा, कैथ-

लैब के उद्घाटन से, दक्षिण कश्मीर के लोगों

को उनके दरवाजे के नजदीक, खासकर हृदय देखभाल के मामले में सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल सेवाएं मिलेंगी।

मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार जनता को उनके दरवाजे के पास विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को लोगों का विश्वास

कायम रखना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि जनशक्ति की कमी है, उन्होंने आश्वासन दिया कि इन कमियों को जल्द ही दूर किया जाएगा।

मंत्री ने दक्षिण कश्मीर के लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जीएमसी अनंतनाग और उससे जुड़े अस्पताल के प्रशासन और कर्मचारियों की भी सहायता की।

इस अवसर पर जीएमसी अनंतनाग की प्रिसिपल और डॉन डॉ. रुखसाना नजीब ने जीएमसी अनंतनाग में किए गए कारों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जनशक्ति और बुनियादी ढांचे के उत्त्यन के लिए जीएमसी अनंतनाग को उल्लेखनीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने दक्षिण कश्मीर के लोगों को उनके दरवाजे के नजदीक सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने के लिए भी बधाई दी। बाद में, मंत्री ने जीएमसी अनंतनाग के हृदय रोग विशेषज्ञों डॉ. सैयद मकबूल, डॉ. शमीम इकबाल और डॉ. शौकत हुसैन शाह को हृदय देखभाल में उनके उत्कृष्ट कार्य और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया।

जावेद डार ने बड़गाम के विकासात्मक परिदृश्य की समीक्षा की

सार्वजनिक सेवाओं में जीवंतता, पारिस्थितिकी के अनुरूप विकास, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया गया

बड़गाम

कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, सहकारिता और चुनाव विभाग के मंत्री जावेद अहमद डार ने जिले के विकासात्मक परिदृश्य का आकलन करने के लिए बड़गाम में एक समीक्षा बैठक की अवधिकारी की।

शुरूआत में, मंत्री ने प्रमुख चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया, जिसमें 125 बिस्तरों वाले जिला अस्पताल की स्थापना, रेशीपोरा में 100 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केरर अस्पताल, सड़क के बुनियादी ढांचे, चंदूरा में नए बस टर्मिनल, यूसमार्ग और दूधपथरी सहित पर्यटन स्थलों पर मजबूत मोबाइल कनेक्टिविटी और कृषि और संबद्ध क्षेत्र की योजनाओं का सफल कार्यान्वयन शामिल है।

बैठक में डीडीसी के अध्यक्ष नजीर अहमद खान, बीरवाह के विधायक डॉ. शफी वानी, चंदूरा के विधायक अली मोहम्मद डार और खानसाहिब के विधायक सैफ-उद-दीन भट्ट भी शामिल हुए।

शुरूआत में, बड़गाम के उपर्युक्त अक्षय लाल्क ने मंत्री को जिले में विभिन्न प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं और चल रहे कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जन कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में भी विचार-विमर्श किया।

सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के महत्व पर जोर देते हुए, मंत्री ने लाभार्थी कवरेज को अधिकतम करने के लिए समग्र कृषि विकास कार्यक्रम सहित सभी केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेश-स्तरीय पहलों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।



उन्होंने सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया और सभी जन कल्याणकारी पहलों को सीधे लोगों तक ले जाने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ हर नागरिक तक पहुंचे।

मंत्री ने आम जनता को त्वरित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए और अधिक सक्रियता लाने का निर्देश दिया।

जिले में इंटर भट्टों की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि इनके संचालन को

सुनिश्चित किया जाए और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप सख्ती से संचालन किया जाए, साथ ही सख्त निर्देश दिया कि जिले में कोई भी अवैध इंटर भट्टा संचालन की अनुमति नहीं दी जाए।

दुग्ध सहकारी समितियों की स्थिति को हल करते हुए, मंत्री ने अधिकारियों को किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए कृषि जागरूकता शिविर और मेले आयोजित करने का निर्देश दिया।

जमीनी स्तर पर शासन के महत्व प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने निर्देश दिया कि विधायिकों को अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए योजना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को लगातार क्षेत्र का दौरा करने, जनता के साथ बातचीत करने और जमीनी स्तर की चिंताओं को सक्रिय रूप से हल करने का निर्देश दिया।

मंत्री ने कहा, हमारा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और

कश्मीर कोई अपवाद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत, सरकार अपने लोगों की भलाई के लिए अथक प्रयास कर रही है।

उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर जोर देते हुए बड़गाम जिले में समग्र विकास का आह्वान किया और कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

हालाँकि, मंत्री ने जोर देकर कहा कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पारिस्थितिक संतुलन के अनुरूप किया जाना चाहिए और जिले में कहाँ भी विकास के बहाने कोई पर्यावरणीय गिरावट नहीं होती है।

बैठक के दौरान विधायिकों ने निर्वाचन क्षेत्र-विशिष्ट मांगों और मुद्दों में मगाम में ट्रॉमा अस्पताल की स्थापना, दादिना-लखीपोरा सड़क का निर्माण, सब्जी मडियों का निर्माण, नए पशुपालन केंद्र, स्कूल उन्नयन, एड फूड योजना के तहत ग्राम-स्तरीय बिक्री केंद्र, जल जीवन मिशन के तहत तोसामैदान को शामिल करना, दूधपथरी और तोसामैदान के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, मुजपथरी से दूधपथरी तक एक वैकल्पिक सड़क का निर्माण आदि शामिल हैं। मांगों को सुनने के बाद, मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी वास्तविक चिंताओं को शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।

बैठक में ग्रामीण विकास निदेशक, पीडल्यूडी कश्मीर के मुख्य अधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रमुख और सभी जिला अधिकारी भी उपस्थित थे।



FIND YOUR PERFECT
WEDDING MAKEUP
LOOK

BOOK AN APPOINTMENT NOW TO AVAIL AMAZING OFFERS

BOOK NOW

① 8082520701 | 9055520701 ② H.O.: BARI BHARAMNA B.O.: GANDHI NAGAR



विधानसभा के अध्यक्ष ने नए विधान सभा परिसर की प्रगति की समीक्षा की

जम्मू

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने जम्मू में नए विधानमंडल परिसर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई।

बैठक में सचिव पीडल्ल्यूडी भूपिंदर कुमार, सचिव कानून, न्याय और संसदीय कार्य अचल सेरी, महानिदेशक बजट मोहम्मद सुल्तान, डीजी कोडस महेश दास, सचिव जेकेलए मनोज कुमार पांडित, मुख्य अधियंत आर एंड बी जम्मू एसई आरएंडबी, साउथ सर्कल जम्मू और संबंधित विभाग और विधानसभा सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। हाल के कैबिनेट निर्यातों के महंजर नए विधानसभा परिसर के निर्माण से संबंधित मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। परियोजना के प्रभारी कार्यकारी अधियंत द्वारा पारपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से परियोजना क्रियान्वयन के विभिन्न



चरणों के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी गई। लोक निर्माण विभाग सचिव ने अध्यक्ष को मत्रिपरिषद द्वारा दिए गए निर्देशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। बताया गया कि शेष कार्य की डीपीआर जांच के लिए आईआईटी जम्मू को सौंप दी गई है। डीपीआर की जांच परियोजना का निर्माण कार्य तुरंत शुरू करने पर जोर दिया।

किनिवादा प्रक्रिया के सभी तौर-तरीके 31 मार्च 2025 तक पूरे कर लिए जाएंगे।

अध्यक्ष ने कार्यकारी एजेंसी को अनुबंध मिलने के बाद 18 महीने के भीतर परियोजना को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए विधानसभा परिसर का निर्माण कार्य तुरंत शुरू करने पर जोर दिया।

कृषि मंत्री ने एचएडीपी, कैपेक्स, सीएसएस कार्यान्वयन के तहत भौतिक, वित्तीय उपलब्धियों की समीक्षा की योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान अधिकारियों को उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया



श्रीनगर

कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जावेद डार ने कृषि निवेशालय लालमंडी के बैठक हॉल में कृषि निवेशक, संयुक्त निवेशक, प्रांतीय प्रमुखों, मुख्य कृषि अधिकारियों, योजना प्रमुखों, कृषि विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और सम्पूर्ण कृषि विकास कार्यक्रम, कैपेक्स और सीएसएस के तहत भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का जायजा लिया।

बैठक के दौरान एचएडीपी के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अलावा कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए जावेद डार ने एचएडीपी और कैपेक्स और सीएसएस की विभिन्न परियोजनाओं के तहत धन के शीघ्र और विवेकपूर्ण व्यय के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एचएडीपी परियोजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के विभिन्न घटकों के तहत आवंटित धनराशि को समयबद्ध तरीके से खर्च किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी खर्चों के दौरान उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के महत्व को दोहराया।

मंत्री ने केसीसी और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों की निगरानी के लिए नवीन पहलों के महत्व को रेखांकित किया। मंत्री ने सब्जी फसलों का नए क्षेत्रों में विस्तार करने को भी कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को

खरीफ फसल सीजन के लिए प्रस्तुतियों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। मंत्री ने विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअल का भी अनावरण किया।

जावेद डार ने अधिकारियों को हर क्षेत्र के किसानों तक पहुंचने और उन्हें एचएडीपी के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से जमीनी स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए किसान समुदायों के साथ मिलकर काम करने को कहा।

इससे पहले कृषि निवेशक कश्मीर मोहम्मद इलियास खतीब ने कश्मीर संभाग में विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में एक विस्तृत पावर प्लाइंट प्रस्तुति दी।

उपायुक्त ने उधमपुर में कृषि ऋण योजनाओं की संतुलि की समीक्षा की

उधमपुर

एचएडीपी के तहत मामलों की लाभार्थी पंजीकरण, मंजूरी और वितरण सहित कृषि ऋण योजनाओं के समग्र कार्यान्वयन की समीक्षा उपायुक्त सलोनी राय ने बैंकों के प्रतिनिधियों के अलावा कृषि और संबद्ध विभागों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में की।

उपायुक्त ने संसाधन ऋण तक किसानों की पहुंच में सुधार और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों और बैंकों से हितधारकों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके सरकार की पहल का सक्रिय रूप से समर्थन करने का आग्रह किया।

उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों और बैंकों को इन योजनाओं के तहत जिले के प्रत्येक किसान और किसान परिवार को कवर करते हुए अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को लक्षित कार्यान्वयन की सुविधा के लिए लाभार्थीयों की क्षेत्रवार सूची तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने विभागों को जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने, इच्छुक लाभार्थीयों की पहचान करने, उन्हें लाभ लेने के लिए प्रेरित करने और एक दिन के भीतर सूची जमा करने का निर्देश दिया।

बैंकों को स्मार्ट कार्ड जारी करने में तेजी लाने और क्रेडिट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नवीनतम डेटा अपडेट करने की सलाह दी गई। उपायुक्त ने किसानों को लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए ब्लॉक-स्टरीय क्रेडिट आउटरीच शिविरों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

उपायुक्त ने कृषक समुदाय को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और सरकारी विभागों के बीच मजबूत समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

उपायुक्त पुंछ ने पीएम गति शक्ति कार्यान्वयन, मास्टर प्लान के निर्माण की समीक्षा की



पुंछ

पुंछ के उपायुक्त विकास कुंडल ने जिला स्तर पर पीएम गति शक्ति के कार्यान्वयन और जिले के लिए मास्टर प्लान तैयार करने पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी भविष्य की योजना गतिविधियों के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे अधिक कुशल, पारदर्शी और समन्वित विकास होने की उम्मीद है।

उपायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि जिले में भविष्य की सभी योजनाएं पीएम गति शक्ति पोर्टल का उपयोग करके की जाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह दृष्टिकोण न केवल परियोजनाओं की योजना और निष्पादन को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि जिले के समग्र विकास पर भी दूरगमी प्रभाव डालेगा, जिससे पारदर्शिता, प्रभावशीलता और हितधारक विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा।

पोर्टल के उपयोग से विकास परियोजनाओं को निर्बाध और जवाबदेह तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी, जिससे अंततः पुंछ के नागरिकों को लाभ होगा।

भारत बीसी के माध्यम से जुड़े विशेषज्ञों ने पीएम गति शक्ति पोर्टल की विशेषताओं और कार्यान्वयनों का व्यापक प्रदर्शन प्रदान किया। डेमो में दिखाया गया कि कैसे पोर्टल वास्तविक समय की निगरानी, प्रभावी परियोजना निष्पादन में सहायता करता है और परियोजनाओं की त्वरित योजना और कार्यान्वयन की सुविधा के लिए अंतर-विभागीय समन्वय को बढ़ाता है।

बैठक में जीएम डीआईसी पुंछ, एसीआर पुंछ, एसीपी, सीएमओ पुंछ, डीएफओ पुंछ, डीआईओ एनआईसी पुंछ, एआरटीओ पुंछ, सीईओ एमसी, एक्सर्सीएन पीडल्ल्यूडी के अतिरिक्त अन्य संबंधित विभागों अधिकारी भी शामिल हुए।

पीएम विश्वकर्मा योजना

उपायुक्त ने जिला पुंछ में कार्यान्वयन की समीक्षा की

पुंछ

उपायुक्त विकास कुंडल ने जिले में पीएम विश्वकर्मा योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की। यह पहल आवश्यक प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और बाजार संपर्क प्रदान करके कारिगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है।

प्रारंभ में, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने उपलब्धियों का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया। उपायुक्त ने लिखित आवेदनों को समयबद्ध तरीके से निपटाने पर जोर देते हुए ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर लाभान्वित व्याक्तियों के बारे में पूछताछ की। लीड बैंक मैनेजर को सभी शाखाओं में लिखित मामलों के निपटारे में तेजी लाने को कहा गया।

इसके अतिरिक्त, बैठक में ब्लॉक-वार लिखित आवेदनों का आकलन किया गया, जिसमें सभी ब्लॉक विकास अधिकारियों ने



अपने-अपने क्षेत्रों से अपडेट प्रदान करने के लिए विडियो कॉन्फैन्स द्वारा भाग लिया। अधिक से अधिक संभाला में कारीगरों को शामिल करने के लिए जन जागरूकता पर जोर दिया गया।

बैठक में पीओ आईसीडीएस, एसीआर, एसीपी, एलडीएम, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिसिपल, बीडीओ, आईटीआई पुंछ और मेंटर के अधीक्षक सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे।

उपायुक्त डोडा ने सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए जन पहुंच शिविर आयोजित किया

डोडा

उपायुक्त हरविंदर सिंह ने कोन्कर्निटिवी में सुधार, स्थानीय मुद्दों को हल करने और जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वजनिक शिकायतों को सुनने और संबोधित करने हेतु मरमट तहसील में पंचायत हब्ल-बी का दौरा किया। उपायुक्त के साथ एनएचआईडीसीएल के अधिकारी, एसपी, तहसीलदार और अन्य विभागों के प्रतिनिधि भी थे। सड़क संरचना, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य नागरिक मुद्दों से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों को विस्तार से सुना गया। निपादन एजेंसियों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के बाद, उपायुक्त ने स्थानीय निवासियों द्वारा उठाए गए कई मुद्दों का समाधान किया। उपायुक्त ने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय के महत्व पर जोर देते हुए शेष शिकायतों के समाधान के लिए समयसीमा निर्धारित की।

सकीना इत्तू ने कुलगाम में एक्सिस बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया

कुलगाम। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू ने कुलगाम का दौरा किया जहां उन्होंने एक्सिस बैंक की एक नई शाखा का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के निवासियों को वित्तीय पहुंच बढ़ाना और व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। उद्घाटन समारोह के दौरान, मंत्री ने आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सुलभ बैंकिंग सुविधाओं के महत्व पर जोर दिया। उद्घाटन में स्थानीय गणमान्य व्यक्ति, बैंक अधिकारी और समुदाय के सदस्य उपस्थित थे।

HELP LINE

Important Telephone Nos.

Civil Secretariat	2547365-69
Jammu University	2435259, 2435248
RRL, Jammu	2544382, 2549051
Army	2432453, 2432653
Municipality Jn. Lines	2578503, 18001803333
Passport Office	2433359

Postal Services

H.P.O. City	2543606
Gandhi Nagar	2435863

Fire Services

City	2544263
Gandhi Nagar	2457705
Canal	2554064
Gangyal	2480026

Cooking Gas dealers

Chenab Gas	2547633
Gulmour Gas	2430835
H.P. Gas	2578456
Jakfed	2548297
Shivangi Gas	2577020
Tawi Gas	2548455

Power House

Gandhi Nagar	2430180
Canal Road	2554147
Janipur	2533359
Nanak Nagar	2430776
Parade	2542289
Satwari (Jammu Cantt.)	2452813

City Hospitals

G.M.C Jammu	2584290, 91, 94, 2584211, 25
GMC Causality	2575364
S.M.G.S. Jmu	2547635, 258477
Govt. Hosp. G. Nagar	2430041, 2431740
Dental Hospital Jmu	2544670
Psychiatric Disease Hos.	2577444
Ascoms Sidhra	262251, 262267, 262536, 39
B.N. Charitable	2555631, 2505310
Vivekanand Hospital	2547418
G.B. Pant Hosp. Satwari	2433500
Military Hospital Sat.	2435572
Police Station, Jammu City	2459777
Bagh-e-Bahu	2459777

CREMATION-SMITI SERVICES JAMMU

SEWA-SAMITI (HEAD OFFICE) 2573905

COURIER SERVICE

BLUE DART	2432806
DHL	94191-90329
AHL	94191-90329
LINKER COURIER	94191-88398
JUST CALL INFO	2476060
NATIONAL HELP DESK CALL	094192-22222
FAROOQ JI (SECRETARY TO ADGP)	9149598407
CHIEF ENGINEER PWD JAMMU	0191-2471788
CHIEF ENGINEER PHE JAMMU	0191-2547586, 2544356
CHIEF ENGINEER PDD JAMMU	0191-2545061
DC OFFICE JAMMU	0191-2544366
RAILWAY ENQUIRY	1800111321
AIRPORT ENQUIRY JAMMU	0191-2437843
ISBT ENQUIRY JAMMU	0191-2435262
RTO JAMMU	0191-2472490
SHARAT CHANDER KHAJURIA	9419127999
AN INTERNATIONAL ACADEMIC SCHOLAR	
PROF. (DR.) KESHAV SHARMA	9469211211
VICE-CHANCELLOR THE ICAI	
UNIVERSITY HIMACHAL PRADESH	
SANJAY GANDOTRA	6006619429
DEFENCE BUSINESS CONSULTANT	
ANIL KAPAH	9419199999
BUSINESS TYCOON AND SECRETARY AMAR SINGH CLUB	
KULDEEP KAUL	9811156926
INTERNATIONAL BUSINESS TYCOON	
BHUPINDER SINGH (IAS)	94190112477
COMMISSIONER HEALTH SERVICES	
BRIJ MOHAN SHARMA	9419144300
CHIEF CONSERVATOR FOREST UDHAMPUR	
S. OPINDERJEET SINGH (KAS)	9419019026
FINANCE DIRECTOR PDD	
DR. ASHOK VAID (ONCOLOGIST)	9810212235
DIRECTOR MADANTA HOSPITAL	
DR. KULBUSHAN GUPTA HOD RADIOLOGY	9419190360
GROUP CAPT. KULOWANT SINGH	7889794904
COL PRITHVIRAJ	9419281250
DR. RAJESH SINGH (VET DOCTOR, CAMEL EXPERT, WORKING WITH SHEIKHS) DUBAI	+971567237345
COL. BRIJ BHUSHAN SINGH	8130702061

सकीना इत्तू ने डी.एच. पोरा निर्वाचन क्षेत्र के विकासात्मक परिदृश्य की समीक्षा की

परियोजनाओं को समर्पित पूरा करने, कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन पर जोर दिया गया

कुलगाम

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कल्गाम जिले के डी.एच. पोरा निर्वाचन क्षेत्र के विकासात्मक परिदृश्य का आकलन करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान, मंत्री ने जल जीवन मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, समग्र कृषि विकास कार्यक्रम, जिला कैपेक्स जैसी विभिन्न प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रगति के संबंध में विस्तृत मूल्यांकन किया।

बैठक के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए सकीना ने निर्वाचन क्षेत्र में सभी विकासात्मक परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर समय पर पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को जिले भर में विशेषकर आगामी खेती के मौसम के दौरान सिंचाई योजनाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

उन्होंने बन विभाग के अधिकारियों से विशेष रूप से सर्दियों के दौरान स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए डी.एच. पोरा निर्वाचन क्षेत्र के सभी ब्लॉकों में लकड़ी डिशो स्थापित करने का भी आह्वान किया।



शिक्षा क्षेत्र के संबंध में, सकीना ने संबंधित अधिकारियों को किए ए के स्थानों पर संचालित होने वाले स्कूल भवनों के निर्माण के लिए भूमि की पहचान करने का निर्देश दिया। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में सुविधाएं बढ़ाने और छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के बारमान सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

मंत्री ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार आम जनता के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचे और कल्याण पहल कार्यक्रमों को प्राथमिकता देकर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक के दौरान, मुख्य योजना अधिकारी ने विभिन्न चल रही परियोजनाओं के भौतिक और वित्तीय मील के पथर का विवरण देते हुए एक व्यापक प्रस्तुति दी।

बैठक में कुलगाम के उपायुक्त अतहर आमिर खान, अतिरिक्त उपायुक्त, डीपीओ, सहायक आयुक्त विकास, सहायक आयुक्त राजस्व, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कार्यकारी अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अन्य अधिकारी शामिल हुए।

बाद में, मंत्री ने उनके मुद्दों और शीघ्र निवारण की मांगों को सुनने के लिए कई सार्वजनिक प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात की।

उपायुक्त ने पुंछ में एनसीडी रक्तीनिंग अभियान का उद्घाटन किया

पुंछ।

उपायुक्त विकास कुंडल ने राष्ट्रीय स्तर के गैर-संचारी रोग स्क्रीनिंग और तपेदिक अभियान का उद्घाटन किया। अभियान का उद्देश्य उच्च रक्ताचाप, मधुमेह और मौखिक और गर्भास्थाय ग्रीवा के कैसर जैसे गैर-संचारी रोगों का पता लगाना है। बस स्टैंड पर मेडिकल कैंप लगाया गया है और स्क्रीनिंग 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। उद्घाटन के अवसर पर, उपायुक्त ने समुदाय को मुफ्त जांच और उपचार का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने शीघ्र पता लगाने के महत्व पर जोर दिया और स्वास्थ्य अधिकारियों से व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए आउटटीच प्रयासों को अधिकतम करने का आग्रह किया। शिविर के दौरान, जिले के भीतर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चिंताओं को संबोधित करते हुए, उपस्थित लोगों को मुफ्त दवाएँ प्रदान की गईं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. परवेज़ अहमद खान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, पुंछ में इसी तरह के शिविर आयोजित किए गए हैं। शिविर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की एक समर्पित टीम मौजूद है, जो जनता को इन बीमारियों के प्रभावी ढंग से प्रबंधन और रोकथाम के बारे में सहायता और शिक्षित करने के लिए तैयार है।

जावेद डार ने बागवानी विभाग के कामकाज की समीक्षा की बेहतर आर्थिक संभावनाओं के लिए उच्च तकनीकी खेती का आह्वान

श्रीनगर

कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जावेद अहमद डार ने बागवानी विभाग कश्मीर की विस्तृत समीक्षा की।

इस संबंध में मंत्री ने यहां बागवानी निदेशालय राजबाग में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मंत्री ने विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के तहत प्रगति का आकलन किया और विभिन्न चुनौतियों पर भी चर्चा की।

मंत्री ने अधिकारियों से जन कल्याण पहलों को प्राथमिकता देने और निर्धारित लक्ष्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन मोड में काम करने पर जोर दिया।

मंत्री ने स्वीकार किया कि बागवानी क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने की काफी संभावनाएँ हैं और यह बेहतर आर्थिक संभावनाओं के साथ ग्रामीण जीवन को ऊपर उठाने में मदद कर सकता है।

मंत्री ने कहा, बागवानी क्षेत्र में ग्रामीण



लोगों को व्यापक रोजगार प्रदान करने के लिए परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने की असीमित गुंजाइश है।

उन्होंने आधुनिक बागवानी विधियों और उच्च घनत्व खेती के उपयोग का आग्रह किया और किसानों को नवीनतम और आधुनिक खेती विधियों के बारे में जागरूकता और तकनीकी मार्गदर्शन दोनों प्रदान करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा, बागवानी उद्योग को

बढ़ावा देने और इस क्षेत्र को उत्पादक और जीवन्त और लाभदायक बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप और आधुनिक वैज्ञानिक अनुप्रयोगों को बढ़ाया जाना चाहिए।

उन्होंने संबंधितों को समग्र कृषि विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न कंद्र प्रायोजित और यूटी-स्तरीय योजनाओं के तहत लाभ सुनिश्चित करने, क्षेत्र में बेहतर उत्पादन और प्रगतिशील खेती के लिए

कृषक समुदाय तक पहुंचने का निर्देश दिया।

प्रारंभ में, मंत्री को कर्मचारियों को मजबूत करने और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित मुद्दों से भी अवगत कराया गया।

बाद में, मंत्री ने कश्मीर संभाग के कृषक समुदाय के लिए सेब के बागानों के प्रबंधन के लिए एचएडीपी और स्प्रे अनुसूची 2025 के तहत उच्च घनत्व

वृक्षारोपण और बगीचों के कायाकल्प को बढ़ावा देने के लिए डिजाइनर पौधों के उत्पादन पर एक पुस्तिका भी जारी की।

इससे पहले, निदेशक बागवानी कश्मीर, जहार अहमद भट्ट ने विभाग का अवलोकन और प्रदर्शन प्रस्तुत किया।

बैठक में उप निदेशक, सहायक निदेशक, मुख्य बागवानी अधिकारी, तकनीकी अधिकारी और विभाग के अन्य संबंधित लोग भी उपस्थित थे।

टीडीए को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाएं-मुख्य सचिव

जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों के लिए सड़क किनारे सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की

नई दिल्ली

मुख्य सचिव अटल डुल्हने जम्मू-कश्मीर में विभिन्न पर्यटन विकास प्राधिकरणों के कामकाज की समीक्षा और उसे मजबूत बनाने के लिए सभी संबंधितों की एक बैठक की अवश्यकता की। उन्होंने इन निकायों की परिचालन दक्षता और संसाधन आधार को बढ़ाकर उन्हें और अधिक सार्थक बनाने की अवश्यकता पर बल दिया।

इस बैठक में प्रमुख सचिव वित्त, आयुक्त सचिव बन, आयुक्त सचिव पर्यटन, आयुक्त सचिव जीडीए, संभागीय आयुक्त, कश्मीर/जम्मू सचिव पीडब्ल्यूडी, सचिव कानून, बीआरओ, एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल के प्रतिनिधि, मुख्य अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल थे।

मुख्य सचिव ने टीडीए को आत्मनिर्भर बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने वित्त और पर्यटन विभागों को संसाधनों का हस्तांतरण सुनिश्चित करने और टीडीए को अपनी परिसंपत्तियों से गजब उत्पन्न करने की क्षमता के साथ सशक्त बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने टीडीए के स्वामित्व वाली भूमि के सीमांकन के निर्णय दिए, जिससे उन्हें इन महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों पर बेहतर नियंत्रण और प्रबंधन मिल सके। अधिकारियों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, उन्होंने अपने संबंधित अधिकारी क्षेत्र में अपने अधिकार को प्रभावी ढंग से स्थापित करने के लिए जनशक्ति और मजबूत प्रवर्तन क्षमताओं में वृद्धि का आह्वान किया। उन्होंने वित्त विभाग को इस



संबंध में सक्रिय कदम उठाने और उनके सतत विकास के लिए हर साल कम से कम एक-दो टीडीए को सहायता प्रदान करने की सलाह दी। संरचित विकास की आवश्यकता को पहचानते हुए, मुख्य सचिव ने व्यवस्थित और सुनियोजित पर्यटन विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टीडीए के लिए एक मास्टर प्लान

तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए अधिक अवसर पैदा करने के लिए ऐसी रणनीतिक योजना की आवश्यकता को रेखांकित किया। सड़क किनारे सुविधाओं के बारे में चिंताओं को हल करते हुए, मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग को

पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए राजमार्ग प्राधिकरणों और लोक निर्माण विभाग के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने उनसे राजमार्गों और पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाली अन्य सड़कों के किनारे सुविधाओं में अंतर की पहचान करने और उसे पाटने का आग्रह किया। इसके अलावा, उन्होंने सड़क किनारे इन सुविधाओं के उचित संचालन और रखरखाव के महत्व पर जोर दिया, ताकि पर्यटकों को निर्बाध और आनंददायक अनुभव मिल सके। उन्होंने दोहराया कि अच्छी तरह से बनाए रखी गई सुविधाएं पर्यटन को बढ़ावा देने और जम्मू और कश्मीर के पर्सन्दीदा पर्यटन स्थल के रूप में समग्र आकर्षण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आयुक्त सचिव, पर्यटन, यश मुदगल ने बैठक में बताया कि विभिन्न पर्यटन स्थलों पर शौचालय सुविधाओं के संचालन और रखरखाव के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावना का पता लगाने के लिए सुलभ इंटरनेशनल पोशेशन सर्विस अॉफिनाइजेशन के साथ परामर्श चल रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि विभाग द्वारा प्रबंधित सभी शौचालय इकाइयों की विस्तृत स्थानवार जनकारी साझा की गई ताकि इन इकाइयों को यहां संचालित करने और बनाए रखने के लिए संगठन की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया जा सके।

सचिव, पीडब्ल्यूडी, भूपंदर कुमार ने जोर देकर कहा कि पीडब्ल्यू विभाग के मुख्य

इंजीनियरों को रणनीतिक स्थानों पर शौचालय परिसरों और पार्किंग स्थलों के निर्माण के लिए अवधारणा योजनाएं विकसित करने का काम सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि आरएंडबी और पर्यटन विभाग प्रमुख राजमार्गों के साथ उन क्षेत्रों का आकलन करने के लिए अंतर विश्लेषण करेंगे, जहां पर्याप्त सुविधाओं की कमी है।

इसके अलावा यह भी बताया गया कि बीआरओ अधिकारियों को एक महीने के भीतर सड़क किनारे सुविधाओं के लिए एक विस्तृत स्थान योजना प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है। एनएचआई को जून 2026 तक सभी गैर-कार्यात्मक सुविधाओं को चालू करने के लिए एनएचआईडीसीएल के साथ मिलकर, नई खुली सोनमर्ग सुरंग और निर्माणाधीन जोजिला सुरंग के बीच एक सड़क किनारे सुविधा परिसर स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

यह भी बताया गया कि काजीगुंड, मरहामा और जजर कोटली में सार्वजनिक शौचालय की सुविधा और अन्य सुविधाएं अप्रैल 2025 तक चालू हो जाएंगी। यह भी बताया गया कि शौचालय सुविधाओं के स्थानों को स्पष्ट रूप से चिह्नित करने और उनकी दूरी को इंगित करने के लिए राजमार्गों के किनारे नए साइनबोर्ड लगाए जाएंगे।

बैठक में बताया गया कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, पटनीटॉप, सनासर, भद्रवाह और दूधपथरी जैसे पर्यटन स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां साल के अधिकांश समय पर्यटकों की आवाजाही अधिक होती है।

वैष्णो देवी से दिल्ली जा रही बस खाई में गिरी, हादसे में एक यात्री की मौत, 16 घायल

जम्मू

माता वैष्णो देवी मंदिर से लौट रही एक बस शनिवार शाम सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली जा रही थी और यह दुर्घटना जम्मू बस स्टैंड से करीब आठ किलोमीटर दूर मांडा के पास हुई। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए पक्षा डंगा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

अधिकारी ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि एक मोड़ पर चालक ने बस पर से कंट्रोल खो दिया और बस खाई में गिर गई। इसके तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। उन्होंने आगे बताया कि 17 लोगों को बचाकर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, जेकेयूटी डिजास्टर रिसांड फोर्स, सिविल डिफेंस के जवान शामिल हुए। जिस जगह पर हादसा हुआ है। वहां पर ज्यादा अंधेरा होने की वजह से यह



नहीं पता चल पा रहा था कि बस में कोई यात्री फंसा हुआ तो नहीं है।

प्रत्यक्षदर्शी ने क्या बताया?

इस बस हादसे पर एक स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी ने एक न्यूज एंजेंसी को बताया, 'मैं पीछे और पुलिसवालों ने पहले ही हमारी

गाड़ी रोक दी थी। हम उधर से किसी तरह लिफ्ट लेकर यहां पर पहुंचे। आकर देखा कि यहां पर गाड़ी गिरी हुई है। पुलिस वाले यहां पर पहुंच गए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे। उन्होंने लोगों को बाहर निकालकर जीएमसी भेजा जा चुका था।'

काबिल-ए-तारीफ है। सीआरपीएफ वाले भी यहां पर आ गए और लोगों को जीएमसी भेजा। जब यहां पर पहुंचा तो ज्यादातर लोगों को निकालकर जीएमसी भेजा जा चुका था।'

घायल लोगों की लिस्ट इस हादसे में घायल होने वाले लोगों में

7 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल हैं। इनकी पहचान अंजलि, नितेश, सुधीर माहेश्वरी, सुभाष, वृद्धा, शुर्ति, ध्रुव, प्राची शर्मा, विनोद कुमार, कार्तिकय त्रिपाठी, कल्याणी शर्मा, हिमांशु, श्रेया, संध्या, अक्षय, आतिश और आकांशा के तौर पर हुई हैं।

जम्मू-कश्मीर हादसे पर सीएम ने जताया दुक्षिण

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को जम्मू में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया। जम्मू-कश्मीर के सीएम ऑफिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'कटरा से दिल्ली जा रहे तीर्थयात्रियों को लेकर मांडा में हुई बस दुर्घटना से बहुत दुख हुआ। इस दुखद घटना में अपनी जान गंवाने वाले ड्राइवर के परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं।' पोस्ट में आगे कहा गया, 'शुक्र है कि सभी घायल यात्री स्थिर हैं और उन्हें चिकित्सा सुविधा मिल रही है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बचाव दल और अधिकारियों के त्वरित और सराहनीय प्रयासों के लिए उनका आभारी हूं। मेरा कार्यालय संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है।'

स्वास्थ्य मंत्री ने बारामुला में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण, शिक्षा विभागों के कामकाज की समीक्षा की

શ્રીનગર

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण एवं शिक्षा मंत्री सकीना इत्तु ने आज नागरिक सचिवालय में बारामुला जिले में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण एवं शिक्षा विभागों के कामकाज एवं प्रदर्शन की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में विधायक उड़ी सजाद अहमद, विधायक वग़ारा-क्रीरी इफ़कान हफ़ीज लोन, विधायक सौपोर इरशाद अहमद कर, विधायक पट्टन जावेद रियाज बेदर, विधायक तंगमर्ग फारस्क अहमद शाह, विधायक बारामुला जावेद हसन बेग, जिला विकास आयुक्त बारामुला मिंगा शेरपा, निदेशक समन्वय, नए मोडिकल कॉलेज, कॉलेजों के अलावा स्वास्थ्य, समाज कल्याण और स्कूल शिक्षा विभागों के विभागाध्यक्ष, निदेशक एस्कोर्ट-एस्प्रेस, सौरा, प्रिसिपल जीएमसी, बारामुला, सीएमओ, बारामुला और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण और शिक्षा विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

जिले भर के अस्पतालों, सीएच्सी और पीएच्सी में स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाओं और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करते हुए, स्कीना इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, पर्याप्त चिकित्सा कर्मचारियों को सुनिश्चित करने और रोगी देखभाल को बढ़ाने के लिए चल रही परियोजनाओं पर काम में तेजी लाने के महत्व पर जोर दिया। मंत्री ने कहा, “ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पहुंच में अंतराल को दूर करें और लोगों को जीवन रक्षक दवाओं के साथ-साथ अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करें।”

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों



से स्वास्थ्य सुविधाओं पर स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए पैरामेडिक्स और डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने का आह्वान किया।

मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी मेडिकल और कैमिस्ट दुकानों का ड्रा ऑडिट करने का निर्देश दिया ताकि अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसे नियत्रित किया जा सके। उहोंने उहें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रतिष्ठान सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, कंयूटरीकृत बिलिंग सिस्टम का कार्यान्वयन और साइक्लोट्रोपिक दवा रिकॉर्ड के खरखाल जैसे नियमों का पालन किया

जाए।

जिले में समाज कल्याण विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए, मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों और महिलाओं के लिए विभिन्न लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के कार्यान्वयन का आकलन किया। उन्होंने वित्तीय सहायता वितरित करने में पारदर्शिता और दक्षता लाने तथा लाभार्थियों को बिना किसी देरी के उनके हक का लाभ दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, ताकि

अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

शिक्षा क्षेत्र के संबंध में मंत्री ने शिक्षा के स्तर में सुधार, शिक्षण कर्मचारियों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा डिजिटल शिक्षण संसाधनों में अंतरगत को पाठने पर जोर दिया।

बैठक के दौरान मंत्री ने रेखांकित किया कि उमर के नेतृत्व वाली सरकार सभी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कुशल सेवा वितरण सरकार के लिए सवोपरि है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विधायकों

के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखें तथा सुनिश्चित करें कि उनके संबंधित निवाचन क्षेत्रों में परियोजनाओं और योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए उन्हें विश्वास में लिया जाए।

मंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए।

बैठक के दौरान विधायकों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण और शिक्षा विभागों से संबंधित मुद्दे रखे।

प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री से भेट की सरकार जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध-उपमुख्यमंत्री

सरकार जनता को समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध-उपमुख्यमंत्री

३८४

उम्मुख्यमंत्री सुरिंदर चैधरी ने जनता की समस्याओं को कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि इनके निवारण के लिए प्रभावी तत्र बनाया गया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधितों को आवश्यक निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं कि सार्वजनिक शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और विकासात्मक पहलों में तेजी लाई जाए। हम विकास और अच्यूतैनिक जीवन से संबंधित मुद्दों से अवगत हैं। इनकी निगरानी और त्वरित निष्पादन के लिए एक प्रभावी तत्र स्थापित किया जा रहा है।

उमपुर्वामंत्री ने यह बात नौशेरा, सुंदरबनी और राजौरी जिले के अन्य हिस्सों से आए कई प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत करते हुए कही। जिन्होंने आज उनसे अपने क्षेत्रों और सेवा संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए



मूलाकात की। बाद में, पूर्व विधायकों, सरपंचों, विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों ने भी उपमुख्यमंत्री से मूलाकात की और अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों और क्षेत्रों के विकास संबंधी और अन्य मुद्दों को स्वाक्षर। उपमुख्यमंत्री आशासन का यथाश

मुलाकात की। बाद में, पूर्व विधायकों, सरपंचों, विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों ने भी उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपने-अपने निवाचन क्षेत्रों और क्षेत्रों के विकास संबंधी और अन्य मुद्दों को रखा। उपमुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडलों को आशासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का यथाशीघ्र समाधान किया जाएगा।

युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाया गया है-उपमुख्यमंत्री

जम्मू

इस बात पर जोर देते हुए कि सरकार युवाओं की तकनीकी क्षमताओं को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि युवाओं को आधुनिक और बाजार आधारित तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि वे अपने लिए और अन्य इच्छुक लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकं। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने अखंक रोड जम्मू में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और महिलाओं के लिए सरकारी पालिटेक्निक के अपने व्यापक दौरे के दौरान छात्रों के साथ बातचीत करते हुए यह बात कही। उनके साथ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत है और इस संबंध में उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी ऊर्जा और प्रयासों को मजबूत और समृद्ध देश बनाने के लिए लगाना चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने विभिन्न संकायों में अपने पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया और संसाधनों के सकारात्मक यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उन्हें प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, पुस्तकालय, छात्रावास और अन्य संबंधित सुविधाओं जैसी किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। उपमुख्यमंत्री ने चल रहे बुनियादी ढंगे के कार्यों की गति का निरीक्षण करते हुए इन परिस्परियों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों को प्रदान की जा रही मौजूदा सुविधाओं को बढ़ावे के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री के उपयोग और इनके निर्माण के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करने का उचित ध्यान रखा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जलवायु परिवर्तन जागरूकता पर जोर दिया, जम्मू-कश्मीर में जल संकट के खतरे पर प्रकाश डाला

जम्मू विश्वविद्यालय में एनईपी-2020 पर क्षमता निर्माण कार्यशाला को संबोधित किया, 'डिज़ाइन योर डिग्री' कार्यक्रम की सराहना की

जम्मू

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दोहराया कि जम्मू और कश्मीर जलवायु परिवर्तन से गंभीर खतरे का सामना कर रहा है, खासकर जल संकट के रूप में, उन्होंने अधिक जागरूकता और कारबाई की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने जम्मू विश्वविद्यालय के ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह आॅफिटोरियम में 'एनईपी-2020' के कार्यान्वयन के लिए इनोवेशन पेडगोजी में 'क्षमता निर्माण' पर तीन दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, हम अपने लोगों को जलवायु परिवर्तन के साथ क्या हो रहा है और इससे होने वाले खतरों के बारे में शिक्षित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक नेताओं के रूप में यह जिम्मेदारी हमारी है।'

जलवायु परिवर्तन के गंभीर मुद्दे को हल करते हुए, मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में चिंताजनक वर्षा की कमी पर प्रकाश डाला।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 'डिजाइन योर डिग्री' कार्यक्रम पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने

कार्यशाला का आयोजन मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा कौशल ऊष्मायन, नवाचार, उच्चिता विकास केंद्र, जम्मू विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जम्मू विश्वविद्यालय के उपकूलपति प्रोफेसर उमेश राय, एसएमवीडी विश्वविद्यालय, बीजीएसबीएस विश्वविद्यालय और जम्मू के क्लस्टर विश्वविद्यालय के उपकूलपतियों के साथ-साथ वरिष्ठ संकाय सदस्यों, विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्यों और छात्रों ने भाग लिया।

जलवायु परिवर्तन के गंभीर मुद्दे को हल करते हुए, मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में चिंताजनक वर्षा की कमी पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 'डिजाइन योर डिग्री' कार्यक्रम पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार अपनी शिक्षा को आकार देने, उनके कौशल को बढ़ाने और उन्हरीं नौकरी बाजार की मार्गों के साथ संरेखित करने का अधिकार देती है।

उन्होंने कहा जैसे-जैसे जम्मू और कश्मीर के निजी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, विशेष रूप से उद्योग और पर्यटन में, और जैसे-जैसे यह क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकाकृत होगा, नौकरी के अधिक अवसर सामने आएंगे। जम्मू विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मान्यता मिलने से, प्रासांगिक कौशल से लैस छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। उच्च प्रतिशत हासिल करने के लिए छात्रों पर पड़ने वाले दबाव पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा यह आश्वर्यजनक है कि हम अपने बच्चों

पर कितना दबाव डालते हैं। जब आप दिली विश्वविद्यालय जैसे शीर्ष कॉलेजों के लिए कट-ऑफ प्रतिशत देखते हैं तो यह सवाल उठता है कि 100 प्रतिशत से अधिक क्या है?

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डिज़ाइन योर डिग्री कार्यक्रम छात्रों को उन विषयों का अध्ययन करने की अनुमति देकर शिक्षा में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है जो वास्तव में उनकी रुचि रखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भविष्य की सभावनाओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने शिक्षा और उद्योग पर एआई के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सीखने और काम करने के तरीके को

नया आकार दे रहा है। हालांकि यह शैक्षणिक कार्यों के लिए चैटजीपीटी जैसे टूल का उपयोग करने में आसानी जैसी चुनौतियां पेश करता है, लेकिन यह नवाचार और विकास के लिए अपार अवसर भी प्रदान करता है।

उन्होंने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के मार्गदर्शन में डिज़ाइन योर डिग्री पहल के अग्रदूतों, दिली विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों की भूमिका को स्वीकार किया।

मुख्यमंत्री ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता और विश्वविद्यालय के प्रो-चांसलर के रूप में, जम्मू विश्वविद्यालय को उसके शैक्षणिक प्रयासों में समर्थन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

उन्होंने पुष्टि की, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मैं यहां हूं, मैं जम्मू विश्वविद्यालय को बढ़ाने और फलने-फूलने में मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं वह करूँगा। प्रतिष्ठित एनएसीए मान्यता प्राप्त करने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय के उपकूलपति, संकाय और छात्रों को बधाई देते हुए, सीएम ने तीन दिवसीय कार्यशाला की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने डिज़ाइन योर डिग्री कार्यक्रम के तहत सरकारी महिला कॉलेज परेड और जम्मू विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ भी बातचीत की, जिन्होंने अपने सीखने के अनुभव साझा किए। उन्होंने बातचीत को प्रेरणादायक बताया और युवा और प्रतिभाशाली दिमागों के साथ इस तरह की और भागीदारी के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की।



मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व विचार-विमर्श का समापन किया

किश्तवाड़, डोडा जिलों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्शदात्री बैठकों की अध्यक्षता की

जम्मू

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के नागरिक सचिवालय में जम्मू संभाग के किश्तवाड़ और डोडा जिलों के निवाचित प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकों कर जन प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श का समापन किया।

किश्तवाड़ जिले के सत्र की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नेता सुनील शर्मा, जो जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांडु-नाग्सेनी का प्रतिनिधित्व करते हैं, किश्तवाड़ के जिला विकास परिषद के अध्यक्ष और जिले के विधान सभा के सदस्यों सहित जन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

प्रतिनिधियों ने अपनी मार्गों और मुद्दे प्रस्तुत किए, मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि बजट निर्माण में उनके सुझावों पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-



कश्मीर के सभी 20 जिलों के जन प्रतिनिधियों के साथ परामर्श की श्रृंखला समाप्त हो गई है, जिससे लोगों के सामने आने वाले जमीनी स्तर के मुद्दों पर मूल्यवान सुझाव प्रदान किये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने निवाचित प्रतिनिधियों से कहा ये बातचीत हमें लोगों की प्राथमिकताओं को समझने में मदद करती है। चूंकि आप जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए आपके सुझाव नीति-निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

प्रकार, डोडा जिले के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री के साथ अपनी विकास प्राथमिकताओं और चिंताओं पर चर्चा की। दोनों जिलों के बारे में उड़ाए गए प्रमुख मुद्दों में शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य

देखभाल केंद्रों में कर्मचारियों की कमी, पेयजल आपूर्ति, सड़क कनेक्टिविटी और चैडीकरण, सुरक्षा का निर्माण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार को समाप्त किया गया।

किश्तवाड़ और डोडा के उपायुक्तों ने अपनी प्रस्तुति में विधायकों द्वारा प्राथमिकता दी गई पांचों का निर्वाचन क्षेत्र-वार विवरण प्रदान किया। डीडीसी अध्यक्षों और विधायकों ने बजट निर्माण प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने आग्रह किया कि यह सहभागी वृष्टिकोण एक नियमित सुविधा के रूप में जारी रहना चाहिए। बैठक में मुख्य सचिव अटल दुल्ह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, प्रमुख सचिव वित्त संतोष डी. वैद्य, महानिदेशक बजट एम.एस. मलिक, महानिदेशक व्यव प्रभाग-1 सज्जाद हुसैन गन्डी और अन्य संबोधित अधिकारी भी उपस्थित थे।